नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 198
दि. 22.04.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

खरगे के बयान से सियासी भूचाल, चुनावी माहौल में गरमाई जुबानी जंग; चुनाव आयोग पहुंची भाजपा

नई दिल्ली। देश के चुनावी परिदृश्य में एक बार फिर बयानबाजी ने राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान ने सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए इस बयान को लेकर अब मामला भारतीय जनता पार्टी और भारतीय चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, जिससे यह मुद्दा केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में भी आ गया है। घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब खरगे ने एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री की तुलना 'आतंकवादी' से कर दी। इस टिप्पणी के सामने आते ही राजनीतिक माहौल गरमा गया और भाजपा ने इसे न केवल व्यक्तिगत हमला बताया, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी करार दिया। पार्टी का कहना है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग न केवल प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि चुनावी वातावरण को भी दूषित करता है।

भाजपा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को एक औपचारिक शिकायत सौंपी है। पार्टी ने आयोग से मांग की है कि इस बयान को प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तत्काल संज्ञान लिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि खरगे को या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने या अपने बयान को वापस लेने के लिए निर्देशित किया जाए। भाजपा का तर्क है कि चुनाव के दौरान इस तरह की तीखी और व्यक्तिगत टिप्पणी मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकती है।

इतना ही नहीं, भाजपा ने कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई है। पार्टी ने अपने पत्र में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस मामले में दंडात्मक और नियामक कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा चाहती है कि जांच के बाद यदि कोई अपराध सिद्ध होता है, तो उसके अनुरूप सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह के बयान देने से राजनीतिक दल और नेता बचें।

इसके अलावा भाजपा ने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि इस विवादित बयान के प्रचार-प्रसार पर तुरंत रोक लगाई जाए। पार्टी का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया में इस बयान के लगातार प्रसार से चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है। इसलिए आयोग को निर्देश जारी कर इसे सभी माध्यमों से हटवाना चाहिए।

दूसरी ओर, विवाद बढ़ने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' कहना नहीं था, बल्कि वे उनकी कार्यशैली की आलोचना कर रहे थे। खरगे का कहना है कि उन्होंने यह टिप्पणी उस संदर्भ में की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है।

खरगे ने यह भी कहा कि उनका बयान व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि वह लोकतंत्र में संस्थाओं के उपयोग और कथित 'डर के माहौल' की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया गया था। हालांकि, उनकी इस सफाई के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी मौसम में इस तरह की बयानबाजी नई नहीं है, लेकिन जब यह व्यक्तिगत हमलों के स्तर तक पहुंच जाती है, तो इसका प्रभाव व्यापक होता है। इससे न केवल राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि मतदाताओं के बीच भी भ्रम और ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो सकती है।

अब इस पूरे मामले में अगला कदम भारतीय चुनाव आयोग के निर्णय पर निर्भर करेगा। आयोग यह तय करेगा कि क्या यह बयान वास्तव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और यदि हां, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

फिलहाल, इस विवाद ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। जहां एक ओर भाजपा इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने नेता के बयान को संदर्भ में देखने की बात कह रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है और चुनावी बहस का केंद्र बन सकता है।

फर्जी दस्तावेजों की आड़ में लग्जरी कारों का खेल: 'ऑपरेशन नुमखोर' ने खोला हजारों करोड़ के टैक्स चोरी रैकेट का राज

नई दिल्ली। देश में टैक्स चोरी और तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सिस्टम की कई परतों को एक साथ बेनकाब कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन नुमखोर' ने देश में लग्जरी गाड़ियों की अवैध एंट्री के एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह मामला केवल तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फर्जी दस्तावेज, सिस्टम की कमजोरियां और कथित रूप से प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता जैसे कई गंभीर पहलू सामने आ रहे हैं।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, भूटान से करीब 15,849 लग्जरी गाड़ियां बिना कस्टम ड्यूटी और टैक्स चुकाए भारत में लाई गईं। 'नुमखोर', जिसका भूटानी भाषा में अर्थ 'वाहन' होता है, अब एक ऐसे ऑपरेशन का नाम बन गया है जिसने करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की कहानी उजागर कर दी है। यह पूरा खेल इतनी सफाई से खेला गया कि लंबे समय तक किसी को भनक तक नहीं लगी।

दरअसल, इस रैकेट का तरीका बेहद शातिर था। तस्कर पहले लग्जरी कारों को पूर्वोत्तर सीमाओं के जरिए भारत में लाते थे, खासतौर पर भूटान से सटे इलाकों के रास्ते। इसके बाद इन गाड़ियों को वैध दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। कई गाड़ियों को 'डिस्पोजल व्हीकल' यानी सेना या सरकारी विभाग से बेची गई पुरानी गाड़ी बताकर कागज बनाए गए, तो कुछ को दूतावास या मंत्रालय से जुड़ा दिखाया गया। इन दस्तावेजों की गुणवत्ता इतनी उच्च स्तर की थी कि पहली नजर में असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता था।

जांच की शुरुआत Kerala से हुई, जहां 35-40 लग्जरी कारों की संदिग्ध एंट्री ने अधिकारियों का ध्यान खींचा। जब नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री का डिजिटल ऑडिट किया गया, तो एक के बाद एक परत खुलती चली गई। इसके बाद मामला Assam, Himachal Pradesh और देश के अन्य हिस्सों तक फैल गया। असम में अकेले 464 ऐसे वाहन रजिस्टर्ड पाए गए, जबकि केरल में अब तक 50 से अधिक गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं।

इस पूरे नेटवर्क की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंचता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार, कुछ फिल्मी सितारों ने भी इन गाड़ियों को खरीदा, हालांकि अभी तक किसी का नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच एजेंसियां इस पहलू को लेकर बेहद सतर्क हैं, क्योंकि इसमें हाई-प्रोफाइल नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

'ऑपरेशन नुमखोर' सिर्फ एक राज्य या एक एजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह राष्ट्रीय स्तर की जांच बन चुका है। 20-21 अप्रैल 2026 को केरल के मुन्नार में भारत-भूटान जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। इस बैठक में सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने, कस्टम जांच को सख्त बनाने और ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर चर्चा हुई। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे इस रैकेट से जुड़े और बड़े नाम और नई परतें सामने आ सकती हैं। 'ऑपरेशन नुमखोर' ने यह साफ कर दिया है कि तस्करी का यह खेल केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिस्टम के भीतर तक अपनी जड़ें जमा चुका है—जहां फर्जीवाड़ा, प्रभाव और लालच मिलकर कानून को चुनौती दे रहे हैं।

बंगाल में चौथी बार सत्ता वापसी का दावा हल्दिया रैली से ममता का बड़ा सियासी संदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चुनावी गर्मी के चरम पर है और इसी बीच राज्य की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने हल्दिया की रैली से बड़ा दावा करते हुए साफ कर दिया कि उनकी पार्टी All India Trinamool Congress (टीएमसी) लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने अपने भाषण में न केवल विपक्षी Bharatiya Janata Party (भाजपा) पर तीखा हमला बोला, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की।

रैली में ममता बनर्जी का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में नहीं देखना चाहती और राज्य की जनता विकास, सामाजिक योजनाओं और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पर टीएमसी के साथ खड़ी है। ममता ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने जो काम किए हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं और इसी आधार पर वे एक बार फिर जनता के बीच जा रही हैं।

अपने भाषण में उन्होंने विपक्षी दलों को भी एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी विपक्षी दल एक मंच पर आएं और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती दें। ममता ने 2026 को निर्णायक वर्ष बताते हुए यह दावा भी किया कि भाजपा को न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि दिल्ली की सत्ता से भी बाहर किया जाएगा। यह बयान साफ तौर पर उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और विपक्षी एकता की राजनीति को दर्शाता है।

रैली के दौरान ममता बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष Suvendu Adhikari पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों में अहंकार इतना बढ़ गया है कि पूरा परिवार ही चुनावी मैदान में उतर गया है। उनके इस बयान को राजनीतिक परिवारवाद के आरोपों के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा लगातार टीएमसी पर इस मुद्दे को लेकर हमला करती रही है।

इसके साथ ही ममता ने अपने भतीजे Abhishek Banerjee का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष रोजाना अभिषेक पर व्यक्तिगत हमले करता है, लेकिन वे राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ममता ने संकेत दिया कि आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी को पार्टी और संगठन में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, खासतौर पर मिदनापुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की निगरानी उनके हाथ में होगी।

हल्दिया की इस रैली को केवल एक चुनावी सभा नहीं, बल्कि टीएमसी की रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने भाषण के जरिए साफ कर दिया कि वह इस चुनाव को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहतीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजनीति के बड़े परिप्रेक्ष्य में पेश कर रही हैं। बंगाल की राजनीति में यह मुकाबला जितना स्थानीय मुद्दों पर आधारित है, उतना ही यह केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई का रूप भी लेता जा रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में बयानबाजी और सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है।

अमेरिका-ईरान वार्ता पर संकट के बादल, ट्रंप का दावा मजबूत स्थिति में है अमेरिका; इस्लामाबाद में सन्नाटा

इस्लामाबाद। पश्चिम एशिया की जटिल कूटनीति एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में प्रवेश करती दिख रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की शांति वार्ता अधर में लटकी नजर आ रही है। दो सप्ताह के युद्धविराम की समयसीमा समाप्ति के करीब है, लेकिन दोनों देशों के बीच न तो भरोसे का माहौल बन पाया है और न ही कोई ठोस प्रगति सामने आई है। 11 और 12 अप्रैल को हुई पहले दौर की वार्ता किसी निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए दूसरे दौर की बातचीत के लिए इस्लामाबाद को मंच बनाने की पहल की। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, हजारों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई, और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गईं।

लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद न तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा और न ही ईरानी दल। इस स्थिति ने वार्ता को लेकर गहरे संशय पैदा कर दिए हैं। कुछ संकेत जरूर मिले हैं कि दोनों देशों की सुरक्षा टीमें पहले से पाकिस्तान में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर किसी भी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की अनुपस्थिति ने पूरे प्रयास को ठहराव की स्थिति में ला दिया है।

इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर स्थिति को और राजनीतिक रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका "बहुत मजबूत स्थिति" में है और वह किसी भी समझौते के लिए तैयार है, बशर्ते ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट और सीमित रुख अपनाए। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकला, तो इसका असर वैश्विक तेल कीमतों और शेयर बाजारों पर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, ईरान की रणनीति भी उतनी ही सख्त दिखाई दे रही है। तेहरान अपने भू-राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को एक दबाव के औजार के रूप में देख रहा है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का अहम मार्ग है और यहां किसी भी प्रकार का तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों को तुरंत प्रभावित कर सकता है। ईरान की कोशिश है कि वह एक ऐसा समझौता करे, जिससे उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिले, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर कठोर रोक न लगे।

मंगलवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दोनों देशों के राजदूतों से मुलाकात कर संवाद की संभावनाओं को जीवित रखने की कोशिश की। यह पहल इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अभी भी इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को इच्छुक है। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच जारी तीखी बयानबाजी और अविश्वास ने हालात को और जटिल बना दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह गतिरोध केवल अमेरिका और ईरान के बीच का द्विपक्षीय विवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति जैसे कई बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। अमेरिका जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना चाहता है, वहीं ईरान अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजर इस संभावित वार्ता पर टिकी हुई है। यह उम्मीद अब भी बनी हुई है कि या तो दोनों देश बातचीत के अगले दौर के लिए सहमत होंगे या कम से कम युद्धविराम की अवधि को बढ़ा देंगे, ताकि तनाव को और भड़कने से रोका जा सके। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह साफ है कि शांति की राह आसान नहीं है और आने वाले दिन इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।

संपादकीय

तनावग्रस्त युवा प्रतिभाओं को खोना राष्ट्रीय क्षति

कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दो महीनों के दौरान चार छात्रों द्वारा आत्महत्या करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह संस्थान ही नहीं, शैक्षिक जगत और उनके परिवारों की भी अपूरणीय क्षति है। घटनाएं तकनीकी संस्थानों में तनाव प्रबंधन और मानसिक उपचार की खामियों को भी उजागर करती हैं। कोई व्यक्ति आत्मघाती कदम तब ही उठाता है जब उसे उम्मीद के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। इस घातक कदम को उठाने से पहले वो तनाव के चरम से जूझते हुए किस मानसिक कष्ट से गुजरता होगा, अंदाज लगाना कठिन नहीं है। उसकी मनःस्थिति इतनी हताशा से भरी होती है कि आत्महत्या जैसा पीड़ादायक-घातक रास्ता उसे समाधान नजर आता है। विडंबना है कि हम संभावनाओं के इस दुखद अंत को मूकदर्शक बने देखते हैं। हम आत्महत्या के आंकड़ों व संख्या का जिक्र ही करते हैं, लेकिन उसे पाल-पोसकर बड़ा करने वाले मां-बाप पर हुए वज्रपात का अहसास नहीं करते। उच्च तकनीकी संस्थान की दहलीज तक पहुंचने में बच्चे कितना शरीर को गलाते हैं। उन्हें पालने-पोसने व बड़ा करने में मां-बाप अपना खून पसीना एक कर देते हैं। हर बच्चा चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। उसके इस मुकाम तक पहुंचने में माता-पिता का त्याग शामिल होता है। कई अभिभावक बैंकों से कर्ज लेकर इन तकनीकी संस्थानों में बच्चों का एडमिशन कराते हैं। कई पैरेंट्स इस लायक बनाने के लिये पैसा कोचिंग संस्थानों में बहाते हैं। फिर एक दिन खबर आती है कि उनकी उम्मीदों ने आत्मघात कर लिया। हमें उनके दर्द को अपने दर्द की तरह महसूस करना चाहिए। इन घटनाओं के बाद एनआईटी ने एक पांच सदस्यीय जांच समिति बनायी है। लेकिन क्या समिति उन बच्चों का जीवन लौटा पाएगी? दूसरी ओर राज्यसभा सांसद ज़ॉन ब्रिटास ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से प्रकरण में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं एनआईटी ने छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिये कुछ अलग समितियां भी बनायी हैं। देश के विभिन्न उच्च तकनीकी संस्थानों में छात्रों के आत्मघात की खबरें अकसर आती हैं। कुछ साल पहले शिक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया था कि साल 2018-2023 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों के 98 छात्रों ने आत्महत्या की थी। इनमें सबसे ज्यादा सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी में हुई थी। उसके बाद आत्मघात करने वाले छात्र एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के थे। जाहिर है इन संस्थानों में कुछ तो ऐसा घट रहा है, जिससे हमारी संवेदनशील प्रतिभाएं साम्य नहीं बैठा पा रही हैं। विडंबना यह है कि देश के हर संस्थान व शासन-प्रशासन के स्तर पर आग लगने पर कुआं खोदने की मनोवृत्ति बनी हुई है। इन संस्थानों में पूरे देश की चुनिंदा प्रतिभाएं ही पहुंचती हैं। जो एक गलाकाट स्पर्धा के दौर से गुजरकर यहां तक आती हैं। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा ऐसा है जो बच्चों को किताबी कीड़ा तो बनाता है, लेकिन चुनौतियों से जूझने लायक नहीं बनाता। अब वे शिक्षक भी नहीं रहे जो छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर पढ़ाएं। बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जिनकी प्राथमिकता अपने विषय और वेतन-भत्तों व सुविधाओं तक ही सीमित रह गई है। परवरिश के स्तर पर भी नहीं सिखाया जाता कि जीवन में बुरे से बुरा घटने पर बिना विचलित हुए कैसे उस चुनौती का सामना किया जाए। परिवार की उम्मीदों का बोझ ढोते, ये प्रतिभावान बच्चे जब असफलता के भय से ग्रस्त होते हैं तो आत्महत्या को अंतिम विकल्प के रूप में सोचने लगते हैं। ऐसी घटनाएं होने पर शिक्षण संस्थानों द्वारा फौरी तौर पर जो कदम उठाये जाते हैं, वे कारगर साबित नहीं होते। किसी आत्महत्या का मामला प्रकाश में आने के बाद हाय-तौबा होती है, तब घोषणाएं होती हैं। फिर वही ढाक के तीन पात। तनाव से गुजरते छात्रों पर पैनी नजर रखने की जरूरत होती है। ये बच्चे बेहद संवेदनशील व ईमानदार होते हैं, जो अपने को साबित न कर पाने पर आत्मघात की राह चुन लेते हैं। समय रहते उनकी पहचान करके संस्थान प्रबंधन व अभिभावकों को उनकी मनोवैज्ञानिक सहायता करनी चाहिए। इन प्रतिभाओं को तनाव के दानव का ग्रास बनने से रोके जाने की जरूरत है।

स्त्रियों से राजनीतिक छल अब चलेगा नहीं

> स्त्रियों की राजनीतिक अभिलाषाएं आज उस सुप्तावस्था में नहीं हैं, जो नब्बे के दशक में थीं। साफ है कि यह विधेयक राजनीतिक गतिविधि मात्र थी। जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बन गई, वह बताता है कि बीजेपी इसकी तैयारी के साथ आई थी।

भारत में महिला आरक्षण को लेकर एक साथ कई सवाल हैं। पहला है कि संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया, या उसे पास कराने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी? साफ है कि बीजेपी का इरादा इस मसले को उठाना, विरोधियों को उत्तेजित करना था, ताकि वे शोर मचाएं। भारतीय राजनीति विश्वसनीय नहीं है। सरकार जानती थी कि उसके साथ दो-तिहाई सदस्य नहीं हैं और आज के राजनीतिक हालात में उसे कतई आशा नहीं करनी चाहिए थी कि विरोधी राजनीति का कोई धड़ा उसके समर्थन में आता। तब फिर क्यों बिल पेश किया?

फौरी तौर पर यह राजनीतिक तीर था, जो 'नारी-शक्ति' का लाभ उठाने के लिए चलाया गया था। संसद में जब बातें होती हैं, तब उन्हें गांव-गांव में सुना जाता है। विरोध में जितना शोर होगा, फायदा उतना ज्यादा होगा। उद्देश्य माहौल बनाना, नैरेटिव रचना या इसे जो भी कहें, उतना ही था। विरोधियों की दिलचस्पी भी कम से कम महिला आरक्षण में नहीं थी। परिसीमन को लेकर भी उनके तर्क विचित्र थे। इससे ज्यादा उनका इरादा भी कुछ नहीं था। बहरहाल, इसका विपरीत-प्रभाव भी होगा, जो समूची राजनीति को अपनी चपेट में लेगा।क्या महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें छला जा रहा है? यह दीगर सवाल है कि इस विधेयक के परास्त होने का लाभ बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में मिलेगा या नहीं। असल बात यह है कि देश की राजनीति ने पिछले तीन दशक से 'नारी-शक्ति' को छला है। उसे बहुत ज्यादा छला नहीं जा सकेगा। स्त्रियों की राजनीतिक अभिलाषाएं आज उस सुप्तावस्था में नहीं हैं, जो नब्बे के दशक में थीं। साफ है कि यह विधेयक राजनीतिक-गतिविधि मात्र थी। जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बन गई, वह बताता है कि बीजेपी

इसकी तैयारी के साथ आई थी।

सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक, 1996 के रूप में 12 सितंबर, 1996 को महिला आरक्षण विधेयक, पेश किया था। विधेयक पेश तो हुआ, लेकिन राजनीतिक आम सहमति न बनने और गठबंधन सरकार के भीतर विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा और 11वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही लैप्स हो गया। देश की राजनीति चाहती, तो देवेगौड़ा का बिल ही पास हो जाता।

सरकार ने इसबार जो विधेयक पेश किया था, वह संसदीय सीटों के परिसीमन पर केंद्रित था। उसके विरोधियों का कहना है कि परिसीमन देश को तोड़ देगा। वे कहते हैं कि 2023 के बिल को लागू करो। वर्ष 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, इसे परिसीमन के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होने की शर्त से बंधा हुआ है। परिसीमन रुकेगा तो आरक्षण भी रुकेगा।

सरकार ने 2023 के बिल की अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि वह लैप्स न हो। उसकी प्रक्रिया ठीक से चली भी तो 2034 के चुनाव के पहले आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा। संभव है कि 2039 में लागू हो। क्या महिलाएं इतना लंबा इंतज़ार करेंगी? दरअसल, देश की पुरुष-संचालित राजनीति देख नहीं पा रही है कि महिलाएं धीरे-धीरे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर आ रही हैं। यह ताकत अभी तक वोटर के रूप में है, पर जल्द ही नेतृत्व के लेवल पर भी दिखाई पड़ेगी।

जब 2023 का वह बिल पास हो रहा था, तब उसे लेकर जबर्दस्त सर्वानुमति थी। वह सर्वानुमति भी राजनीतिक-लाभ लेने तक की थी। उस वक्त भी सवाल था कि इसे फौरन लागू करने से रोका किसने है? कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में कहा था, जब सरकार नोटबंदी जैसा फैसला तुरत लागू करा सकती है, तब इतने महत्वपूर्ण विधेयक की याद साढ़े नौ साल बाद क्यों आई? बात तो बहुत मार्के की कही थी, पर दस साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वह भी तो उसे लागू नहीं करा पाई। यूपीए के सहयोगी दल ही इसके लिए तैयार नहीं थे।

'इंडिया' ब्लॉक के नेता आज कह रहे हैं कि हम उस विधेयक का समर्थन करेंगे जो 543 सीटों की वर्तमान संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत लागू कराए। उन्होंने क्या सरकार के साथ बैठकर इस विषय पर बात की? जब वे जानते हैं कि जनगणना और परिसीमन के बिना यह फिलहाल कानूनी रूप से संभव नहीं है, तो उन्हें ऐसी पेशकश करनी चाहिए, जिसके पीछे ईमानदारी हो और व्यावहारिकता भी।

व्यावहारिक बात है कि सांसदों की वर्तमान संख्या को देखते हुए, किसी पार्टी का सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा में मोटे तौर पर 86 प्रतिशत पुरुष हैं और देश की विधानसभाओं में करीब 90 प्रतिशत। इसी संख्या पर आरक्षण लागू हुआ, तो बड़ी संख्या में पुरुषों का पत्ता साफ हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि उसका चुनाव-क्षेत्र आरक्षण के दायरे में चला जाए। भले ही एक-तिहाई सीटें महिलाओं के कोटे में जाएंगी, पर किसका क्षेत्र छिनेगा, पता नहीं। एक-एक चुनाव क्षेत्र को तैयार करने में बरसों की मेहनत और लाखों की रकम खर्च होती है। यह सब उन्हें मंजूर होता, तो 1996 से अब तक यह सब रुका हुआ क्यों है?

बहरहाल, पुरुषों की इस राजनीति को महिलाओं की बढ़ती ताकत ही ठिकाने लगाएगी। अभी तक माना जाता था कि महिलाओं की राजनीतिक आवाज़ नहीं होती है। वोटर के रूप में उनकी आवाज़ को मान्यता मिल चुकी है। कौन-सा राज्य है, जहां पार्टियां महिलाओं को लिए लुभावने कार्यक्रम लेकर नहीं आ रही हैं। ये कार्यक्रम वोटर के रूप में हैं।

दूसरी तरफ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में भी महिलाओं के बीच खामोश क्रांति हो रही है। इसकी शुरुआत स्थानीय निकायों, यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में, महिलाओं को न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने से हुई है, जो 1993 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत उन्हें प्राप्त हुआ है। इस आरक्षण को बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित 20 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। जमीनी स्तर पर अब करीब साढ़े चौदह लाख से अधिक महिलाएं जन-प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं, जो इन निकायों के कुल सदस्यों का करीब 46 प्रतिशत है। इनमें से कुछ अपने पतियों, भाइयों और बेटों के लिए आड़ का काम कर रही हैं, पर ज्यादा बड़ी संख्या उन महिलाओं की है, जो न केवल सक्रिय हैं, बल्कि अपनी कुशलता साबित कर रही हैं।

इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जन्म ले रही हैं। ग्राम सभा की सदस्य, जिला स्तर पर जाना चाहती हैं, नगरपालिका की पार्षद विधायक और उससे ऊपर के स्तर पर। उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी भी सामने आ रही है। स्थानीय निकायों के कुल सदस्यों में 46 प्रतिशत महिलाएं हैं, वहीं लोकसभा और विधानसभाओं में यह प्रतिशत काफी कम है। 18वीं लोकसभा में 543 में से 75 महिला सांसद (लगभग 14 प्रतिशत) हैं, जो 2024 में चुनाव लड़कर आई हैं। राज्यसभा में लगभग 39 (17 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं। वहीं एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 4,666 सांसदों/विधायकों में से केवल 464 यानी 10 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह असंतुलन है, जिसे अब महिलाएं ही आगे बढ़कर दूर करेंगी।

प्रेरणा

अटूट विश्वास की प्यास और आत्मा की सच्ची साधना

भक्ति मनुष्य के जीवन की सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली अवस्था है, जहाँ वह अपने भीतर के अहंकार, इच्छाओं और भ्रमों को पार करके किसी उच्च सत्य से जुड़ने की कोशिश करता है। यह केवल पूजा या धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक अस्तित्व के करीब ले जाती है। इसी गहन भक्ति के स्वरूप को समझाने के लिए संत कबीर ने एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया, जो हर युग में उतना ही प्रासंगिक रहता है।

एक दिन कबीर अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। वातावरण में एक गहरी शांति थी, और चारों ओर प्रकृति अपनी सहज लय में बह रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से पक्षी पर पड़ी, जो अत्यंत व्याकुल और बेचैन दिखाई दे रहा था। वह पपीहा था, जिसे भारतीय परंपरा में एक विशेष प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि यह पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद ही पीता है और किसी अन्य जल को ग्रहण नहीं करता, चाहे वह कितना ही प्यासा क्यों न हो।

वह पपीहा प्यास से तड़प रहा था और असंतुलन के कारण पानी में गिर पड़ा था। उसके चारों ओर जल ही जल था, उसकी प्यास बुझाने के लिए हर संभव साधन उपलब्ध था, लेकिन उसने अपनी चोंच तक नहीं खोली। वह संघर्ष कर रहा था, पर अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हो रहा था। उसकी यह स्थिति देखकर कबीर और उनके शिष्य गहराई से प्रभावित हुए।

कबीर ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा कि इस छोटे से जीव में जो निष्ठा और समर्पण दिखाई देता है, वह हमें बहुत बड़ा पाठ सिखाता है। उन्होंने कहा कि जब वे इस पपीहे की स्वाति की बूंद के प्रति अटूट लगन को देखते हैं, तो उन्हें अपनी भक्ति भी बहुत क्षीण और अधूरी लगती है। यह पक्षी हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है—जहाँ कोई विकल्प नहीं होता, कोई समझौता नहीं होता, केवल एक ही लक्ष्य होता है और उसी के लिए पूरा अस्तित्व समर्पित होता है।

यह प्रसंग केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए एक गहरा दार्शनिक संकेत है। आज का मनुष्य हर चीज को आसान और त्वरित तरीके से पाना चाहता है। वह थोड़ी सी कठिनाई आने पर ही अपने मार्ग को बदल देता है और किसी दूसरे विकल्प की तलाश करने लगता है। लेकिन पपीहा हमें यह सिखाता है कि यदि हमारा लक्ष्य उच्च और सच्चा है, तो उसके लिए धैर्य और दृढ़ता भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए।

भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम जपना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर उस गहरी लालसा को जगाना है, जो हमें अपने परम सत्य की ओर खींचती है। यह लालसा ही साधक को साधारण से असाधारण बनाती है। जब यह भावना प्रबल होती है, तब व्यक्ति के लिए संसार के सभी आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और वह केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लीन हो जाता है।

कबीर ने इस प्रसंग के माध्यम से यह भी बताया कि सच्ची भक्ति में धैर्य का विशेष महत्व होता है। पपीहा महीनों तक स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा करता है, वह अपनी प्यास को सहन करता है, लेकिन अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता। उसी प्रकार, एक सच्चा साधक भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वह यह जानता है कि सही समय आने पर उसे उसका फल अवश्य मिलेगा।

इस कहानी का एक और गहरा संदेश यह है कि सच्ची भक्ति में कोई द्वंद्व नहीं होता। जब तक हमारे मन में यह विचार रहता है कि यदि यह मार्ग कठिन हो जाए तो हम कोई दूसरा रास्ता चुन लेंगे, तब तक हमारी भक्ति अधूरी रहती है। सच्चा साधक वही होता है, जो हर परिस्थिति में अपने मार्ग पर अडिग रहता है और किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से नहीं डिगता।

आज के आधुनिक युग में, जहाँ भौतिकता और तात्कालिक सुखों का प्रभाव बहुत अधिक है, यह कथा हमें एक गहरी चेतावनी भी देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपने जीवन के उद्देश्य को समझ रहे हैं, या फिर हम केवल बाहरी आकर्षणों में उलझकर अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। पपीहा हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे भीतर सच्ची लगन और निष्ठा है, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

यह प्रसंग हमें आत्मनिरीक्षण के लिए भी प्रेरित करता है। यह हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है और यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हमारी भक्ति भी इतनी ही शुद्ध और अटूट है। यदि नहीं, तो हमें अपने भीतर उस भावना को विकसित करने की आवश्यकता है, जो हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित बना सके।

भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है, जो अपने भीतर सच्ची लगन और अटूट विश्वास रखते हैं। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती वास्तव में हमारे लिए एक अवसर है, जो हमें और अधिक मजबूत और दृढ़ बनाती है। अंततः, पपीहे की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है। यह केवल बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की एक गहरी अनुभूति है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जब हम अपने जीवन में इस भावना को अपनाते हैं, तब हम न केवल अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार, यह छोटी सी कहानी हमें एक बड़ा जीवन दर्शन प्रदान करती है। यह हमें यह समझाती है कि यदि हमारे भीतर सच्ची प्यास, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण है, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही सच्ची भक्ति है, यही आत्मा की साधना है, और यही वह मार्ग है जो हमें हमारे परम सत्य तक पहुंचाता है।

आतंक के खिलाफ मजबूत मोर्चा

भारत दशकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आतंकवाद का सामना करता आया है। यह लड़ाई हमारे लिए नई नहीं है। आतंकवाद कितना वीभत्स हो सकता है, इसका एक उदाहरण पिछले वर्ष पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था, जिसमें लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा गया था।

चूंकि पहलगाम हमले की बरसी निकट है, इसलिए हमें आतंकवाद के खतरों को लेकर सचेत रहना होगा। पहले जहां आतंकवाद सीमांत क्षेत्रों और पारंपरिक तरीकों तक सीमित था, वहीं अब यह उच्च तकनीक, इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के सहारे तेजी से फैलने वाला वैश्विक खतरा बन गया है।

आज आतंकी केवल हथियारों के सहारे नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों, गुप्त वित्तीय नेटवर्कों और वैचारिक प्रचार के जरिये भी काम कर रहे हैं। इस बदलते स्वरूप को समझे बिना आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटना संभव नहीं है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक समयानुकूल पहल की है। इसे नाम दिया है 'प्रहार' (यानी प्रोएक्टिव रिस्पांस अगेंस्ट होस्टाइल एक्ट्स)। यह कदम आतंकवाद से निपटने में बाजी पलटने वाला दांव सिद्ध हो सकता है।

भारत ने आतंकवाद से लड़ते हुए कई अनुभव हासिल किए हैं। इस क्रम में माओवाद से निपटने में अपनाई गई 'समाधान' संकल्पना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दृढ़ इच्छाशक्ति, स्पष्ट रणनीति, बेहतर समन्वय और मजबूत खुफिया तंत्र के माध्यम से उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित किया गया।

इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि नीति स्पष्ट हो और एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत हो, तो जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि आतंक से निपटने में आज की चुनौतियां कहीं अधिक विकराल हैं। आतंकवाद मुख्यतः बाहरी ताकतों द्वारा पोषित है। अब बिखरे हुए छोटे-छोटे समूहों, अकेले काम करने वाले व्यक्तियों और आनलाइन नेटवर्क के रूप में भी वह विस्तार ले रहा है। इस तरह यह एक साथ जमीनी, इंटरनेट और वित्तीय तंत्र तीनों स्तरों पर काम करता है। ऐसे में अलग-अलग और असंगठित प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे।

प्रहार जैसी संकल्पना इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह तकनीक, खुफिया जानकारी, कानून व्यवस्था, वित्तीय निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में समन्वयन को सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है-खतरे को चिह्नित करना, उसे बढ़ने से रोकना और जरूरत पड़ने पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करना। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका समग्र दृष्टिकोण है। आतंकवाद बंदूक या बम का मामला नहीं है, बल्कि यह एक सोच, एक बड़े नेटवर्क और दुश्मन के सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। प्रहार सात मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो इसे एक संतुलित और प्रभावी नीति बनाते हैं। एक स्तंभ है रोकथाम यानी खुफिया जानकारी के आधार पर समय रहते कार्रवाई। दूसरा स्तंभ है प्रतिक्रिया, जिसमें किसी घटना पर त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई। तीसरा स्तंभ है विश्लेषण, जिसमें सटीक जानकारी एवं विश्लेषण के आधार पर निर्णय। चौथा स्तंभ है मानवाधिकार अनुपालन यानी कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई। पांचवां स्तंभ है आतंकी वित्तीय ढांचे की कमर तोड़ना, ताकि उन तक वित्तीय मदद पहुंचने ही न पाए। छठा स्तंभ है जागरूकता और कट्टरता-निरोध, जिसमें समाज को साथ लेकर चलना और दुष्प्रचार का समय से खंडन। सातवां स्तंभ है लचीलापन और पुनर्बहाली यानी घटना के बाद तेजी से सामान्य स्थिति बहाल करना। ये सभी स्तंभ ऐसी रणनीति बनाते हैं, जो न केवल आतंक को रोकने में सक्षम है, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाती है।

आज आतंकी नई तकनीकों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं रह गई है। प्रहार इस कमी को दूर करते हुए साइबर क्षमता, आधुनिक तकनीक और वित्तीय निगरानी को भी अपने ढांचे में शामिल करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंक के खिलाफ अपना रुख और स्पष्ट किया है।

बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर आपरेशन सिंदूर और देश के भीतर आतंकी नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई यह दिखाती है कि भारत अब केवल बचाव की नीति तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर उसके पास निर्णायक और पूर्व-निषेधात्मक कठोर कदम उठाने की क्षमता और इच्छाशक्ति दोनों मौजूद हैं।

प्रहार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी कार्रवाई केवल परिस्थितियों पर निर्भर न रहे, बल्कि एक व्यवस्थित नीति के तहत की जाए। इस नीति का केंद्रीय आधार आतंक की रोकथाम है। इसके लिए खतरे को प्रारंभिक स्तर पर ही चिह्नित कर उसे निष्प्रभावी करना मूल उद्देश्य है। इसके लिए खुफिया-आधारित पुलिसिंग को सुदृढ़ करना, एजेंसियों के बीच रियल-टाइम सूचना साझाकरण सुनिश्चित करना, भर्ती नेटवर्क को समय रहते ध्वस्त करना और आतंकी समर्थन तंत्र को समाप्त करना अनिवार्य है।

साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कट्टरपंथी गतिविधियों की निगरानी और आतंकी वित्तपोषण के स्रोतों पर कठोर नियंत्रण इस ढांचे के प्रमुख घटक हैं। एआइ के माध्यम से संभावित खतरों का पूर्वानुमान, बिग डाटा से संदिग्ध पैटर्न की पहचान, सीमाओं पर ड्रोन निगरानी और साइबर फोरेंसिक के माध्यम से इन्क्रिप्टेड संचार की ट्रैकिंग जैसे उपाय इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। आतंकवाद के डिजिटल स्वरूप को देखते हुए साइबर क्षमताओं का विस्तार अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि डीपफेक आधारित दुष्प्रचार के बढ़ते उपयोग ने यह चुनौती और जटिल बना दी है। यह भी समझना होगा कि कट्टरपंथ केवल सुरक्षा बलों के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज, शिक्षकों, धार्मिक नेतृत्व और नागरिक संगठनों की भागीदारी भी अपरिहार्य है। प्रहार भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसका ढांचा मजबूत है और सरकार की मंशा भी स्पष्ट दिखती है, पर इसकी सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। नीति बनाना पहला कदम है, उसे जमीन पर प्रभावी बनाना असली चुनौती है।

अभियान

कान्हा के चरणों की यात्रा और भक्ति में डूबी दिव्यता का अनुभव

भगवान श्रीकृष्ण का जीवन केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, करुणा, कर्तव्य और वैराग्य का ऐसा अद्भुत संगम है जो हर युग में मानव हृदय को छूता है। महाभारत और पुराणों में वर्णित उनका लगभग 125 वर्षों का जीवन किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सतत यात्रा थी—जन्म से लेकर लीला-विलास, फिर धर्म स्थापना और अंततः वैराग्य तक। इस पूरी यात्रा में भारतभूमि के कई ऐसे पवित्र स्थल हैं, जहाँ आज भी उनकी दिव्यता की अनुभूति की जा सकती है। इन धामों की यात्रा केवल भौगोलिक भ्रमण नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक उतरने वाली भक्ति की साधना है, जहाँ हर कदम पर कान्हा की उपस्थिति का एहसास होता है। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जहाँ आज भी उनकी जन्मभूमि मंदिर में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यह वही स्थान है जहाँ कारागार की कठिन परिस्थितियों में भी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वासुदेव-देवकी के पुत्र ने संसार को नई दिशा

देने के लिए अवतार लिया। मथुरा का विश्राम घाट भी उस शांति का प्रतीक है, जहाँ आकर भक्त अपने मन की व्याकुलता को शांत कर लेते हैं। यहाँ की हवा में आज भी जन्म की उस अलौकिक घटना की गूंज सुनाई देती है।

जन्म के बाद गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के स्नेह में श्रीकृष्ण का पालन-पोषण हुआ। गोकुल की गलियों में आज भी वह निश्छल बाल लीला जीवित है, जहाँ माखन चुराने की मधुर कथाएँ और यशोदा की ममता भरी लोरियाँ हर घर में सुनाई देती हैं। नंद भवन और रमणरेती जैसे स्थान केवल तीर्थ नहीं, बल्कि उस बाल्य प्रेम के साक्षी हैं, जहाँ ईश्वर ने मानव रूप में सरलता और आनंद का संदेश दिया।

वृंदावन वह भूमि है जहाँ भक्ति अपने चरम पर पहुँचती है। यहाँ राधा-कृष्ण की रासलीलाएँ केवल कथाएँ नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक हैं। बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर में जब आरती होती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं कान्हा भक्तों के बीच उपस्थित हों। वृंदावन की रातें विशेष रूप से रहस्यमयी और दिव्य मानी जाती हैं, जहाँ हर कण में राधा रानी और गोपियों की उपस्थिति का अनुभव होता है। यहाँ भक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि जीवंत अनुभूति बन जाती है।

नंदगांव में श्रीकृष्ण का किशोर रूप झलकता है, जहाँ उनकी सरलता और चंचलता का संगम दिखाई देता है। नंद राय मंदिर इस बात का साक्षी है कि कैसे एक साधारण जीवन में भी दिव्यता का वास हो सकता है। वहीं बरसाना, जो राधा जी की नगरी मानी जाती है, प्रेम और भक्ति की चरम अभिव्यक्ति है। लाडली जी का मंदिर और लठमार होली की परंपरा केवल उत्सव नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम की झलक है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। श्रीकृष्ण का जीवन केवल प्रेम और लीलाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने ज्ञान और कर्तव्य का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उज्जैन में गुरु संदीपनि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। यह स्थान आज भी उस गुरु-शिष्य परंपरा का प्रतीक है, जहाँ ज्ञान को जीवन का आधार माना गया। यहीं पर उनकी मित्रता सुदामा से हुई, जो सच्चे प्रेम और समर्पण की अनूठी मिसाल है।

जब जीवन में संघर्ष और जिम्मेदारियाँ बढ़ीं, तो श्रीकृष्ण ने द्वारका को अपनी कर्मभूमि बनाया। द्वारकाधीश मंदिर आज भी उस राजसी और दिव्य जीवन का प्रतीक है, जहाँ उन्होंने एक आदर्श शासक के रूप में धर्म की स्थापना की। द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ कर्तव्य और भक्ति का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है।

कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहाँ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता का ज्ञान दिया। ज्योतिसर में दिया गया यह उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए मार्गदर्शन है। यहाँ आकर यह एहसास होता है कि भक्ति केवल प्रेम नहीं, बल्कि धर्म और कर्म का पालन भी है।

अंततः श्रीकृष्ण ने सोमनाथ के प्रभास क्षेत्र में अपने देह का त्याग किया। यह स्थान वैराग्य और अंतिम सत्य का प्रतीक है, जहाँ जीवन की सभी लीलाएँ समाप्त होकर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। सोमनाथ के पास स्थित यह क्षेत्र आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहाँ आकर मनुष्य जीवन के अंतिम सत्य को समझने का प्रयास करता है।

इन सभी धामों की यात्रा केवल स्थानों का भ्रमण नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक है, जो जन्म से लेकर मोक्ष तक चलती है। श्रीकृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, कर्तव्य, ज्ञान और वैराग्य—ये सभी जीवन के आवश्यक अंग हैं, और इनका संतुलन ही सच्ची भक्ति है। जब हम इन धामों में जाते हैं, तो हमें केवल मंदिरों के दर्शन नहीं होते, बल्कि हमें अपने भीतर उस दिव्यता की अनुभूति होती है, जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है।

कान्हा के इन पवित्र धामों में आज भी वही ऊर्जा, वही प्रेम और वही भक्ति प्रवाहित होती है, जो हजारों वर्षों पहले थी। यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि भगवान कहीं दूर नहीं हैं, बल्कि वे हर उस स्थान पर हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा और प्रेम है। जब मनुष्य अपने भीतर इस भावना को जागृत कर लेता है, तो उसका जीवन भी एक पवित्र यात्रा बन जाता है, जहाँ हर क्षण में उसे ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सूरत कपड़ा बाजार में आग के खतरे पर 'अलर्ट', फोस्टा टोरेंट पावर की संयुक्त रणनीति से बदलेगा सेफ्टी सिस्टम

सूरत। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब माने जाने वाले Surat के कपड़ा बाजार में लगातार सामने आ रही आगजनी की घटनाओं ने अब प्रशासन, व्यापारियों और बिजली कंपनी—तीनों को एक साथ कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में Federation of Surat Textile Traders Association (फोस्टा) और Torrent Power के बीच हुई अहम बैठक ने साफ संकेत दे दिया है कि अब केवल चर्चा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है।

बैठक में जिस सबसे गंभीर मुद्दे ने अधिकारियों और व्यापारियों को चिंतित किया, वह था दुकानों और गोदामों में निर्धारित सीमा से कहीं अधिक बिजली लोड का इस्तेमाल। फोस्टा के महामंत्री दिनेश कटारिया ने स्पष्ट कहा कि बाजार में कई व्यापारी बिना आधिकारिक अनुमति के अतिरिक्त लोड लेकर काम कर रहे हैं, जिससे वायरिंग पर दबाव बढ़ रहा है और शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों का वास्तविक लोड विवरण तुरंत उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते तकनीकी सुधार किए जा सकें और संभावित हादसों को रोका जा सके।

इस बैठक में तकनीकी खामियों पर भी खुलकर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि पारंपरिक तरीके से ब्लैक टेप के जरिए किए जाने वाले वायर जॉइंट अब सबसे बड़ा जोखिम बनते जा रहे हैं। इसके बजाय आधुनिक कनेक्टर और टर्मिनल के

उपयोग पर जोर दिया गया, जो न केवल कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं, बल्कि स्पार्किंग और ढीले तारों की समस्या को भी काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। यह एक छोटा बदलाव जरूर है, लेकिन बड़े हादसों को रोकने में निर्णायक साबित हो सकता है।

Torrent Power के अधिकारियों ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यापारी को अपने प्रतिष्ठान का बिजली लोड बढ़ाना है, तो 10 किलोवाट तक की वृद्धि के लिए प्रक्रिया बेहद सरल है और इसमें ज्यादा कागजी औपचारिकताएं नहीं हैं। इसके बावजूद व्यापारी अनधिकृत तरीके अपनाते हैं, जो अंततः खतरे को बढ़ाते हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि कपड़ा बाजार में आगजनी के पीछे केवल ओवरलोड ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। अस्थायी वायरिंग का अत्यधिक उपयोग, एयर कंडीशनर की नियमित सर्विसिंग का अभाव और पुराने या असुरक्षित विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल—ये सभी मिलकर एक 'टिकिंग टाइम बम' जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की खपत चरम पर होती है, तब यह खतरा और भी बढ़ जाता है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टोरेंट पावर ने पहले ही कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बाजारों में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं, ताकि व्यापारी खुद अपने लोड और वायरिंग की जानकारी साझा करें। इसके साथ ही कई प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरों की मदद से मीटर के बाद की पूरी विद्युत व्यवस्था—जैसे वायरिंग, स्विच, कनेक्शन और अर्थिंग—का निरीक्षण कराया जा रहा है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

बैठक में भविष्य की रणनीति को लेकर भी कई अहम प्रस्ताव सामने आए। इनमें सभी संबंधित पक्षों—व्यापारी संगठनों, बिजली कंपनी और प्रशासन—की संयुक्त बैठकें नियमित रूप से आयोजित करना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दोबारा भरवाना, प्रत्येक दुकान के लोड का वैज्ञानिक विश्लेषण करना और जहां जरूरत हो, वहां तत्काल तकनीकी सुधार लागू करना शामिल है। यह भी तय किया गया कि केवल एक बार की कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए निरंतर निगरानी और जागरूकता अभियान चलाना जरूरी होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूरत का कपड़ा बाजार न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी केंद्र है। ऐसे में यहां बार-बार होने वाली आगजनी की घटनाएं न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका को भी खतरे में डाल देती हैं। इसलिए सुरक्षा उपायों को अब 'विकल्प' नहीं, बल्कि 'अनिवार्यता' के रूप में लागू करना होगा।

बैठक के अंत में सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए केवल तकनीकी सुधार ही नहीं, बल्कि व्यापारियों की मानसिकता में बदलाव भी जरूरी है। जब तक नियमों का पालन स्वेच्छा से नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित नहीं बन सकती। अब देखना होगा कि यह संयुक्त रणनीति जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावशीलता के साथ लागू होती है, क्योंकि सूरत के इस व्यस्त बाजार की

रेलवे जमीन पर 'लकड़ी माफिया' का पर्दाफाश, 22 टन पेड़ों की चोरी में 9 गिरफ्तार

वडोदरा। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई में Railway Protection Force (आरपीएफ) ने संगठित तरीके से पेड़ों की अवैध कटाई और चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में अंकलेश्वर आरपीएफ टीम की इस कार्रवाई ने न केवल रेलवे जमीन पर हो रही अवैध गतिविधियों को उजागर किया है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों की चोरी अब संगठित अपराध का रूप ले चुकी है। पूरा मामला 18 अप्रैल 2026 का है, जब Western Railway के वडोदरा मंडल को कोसाड और गोठनगांव रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई की सूचना मिली। सूचना मिलते ही अंकलेश्वर स्थित आरपीएफ टीम ने बिना समय गंवाए मौके पर छापेमारी की। कार्रवाई इतनी सटीक और तेज थी कि मौके पर ही 9 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जो रेलवे भूमि पर लगे बबूल के पेड़ों को काटकर ट्रकों में भर रहे थे।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से रेलवे की जमीन को निशाना बनाया था, जहां बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर लकड़ी को चोरी-छिपे बाजार में बेचने की तैयारी थी। मौके से कुल 21,985 किलोग्राम लकड़ी बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.31 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे दो ट्रक, एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन और दो कुल्हाड़ियां भी जब्त की गईं। यह दर्शाता है कि गिरोह पूरी तैयारी और आधुनिक उपकरणों के साथ इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहा था।

इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के तहत 19 अप्रैल 2026 को केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि शेष सात आरोपियों को रेलवे न्यायालय से जमानत मिल गई है। हालांकि, आरपीएफ की जांच अभी जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस गिरोह के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि रेलवे भूमि पर इस तरह की अवैध कटाई न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है। बबूल जैसे पेड़ जहां भूमि संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं उनकी इस तरह की अंधाधुंध कटाई से स्थानीय पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की किसी भी अवैध गतिविधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस तरह के मामलों पर और कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि रेलवे भूमि को अतिक्रमण और अवैध दोहन से बचाया जा सके।

यह कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क हैं और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई लंबे समय तक बिना रोक-टोक कैसे चलती रही। आने वाले दिनों में जांच के दौरान इस पूरे नेटवर्क के और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आने की संभावना है।

दूध की पर्ची से लोकतंत्र का संदेश, राजकोट में वोटिंग जागरूकता का अनोखा प्रयोग

राजकोट। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व—चुनाव—को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जहां आमतौर पर रैलियां, पोस्टर और डिजिटल अभियान चलाए जाते हैं, वहीं गुजरात के Rajkot जिले में एक अनोखी और जमीनी पहल ने सबका ध्यान खींचा है। यहां दूध की साधारण पर्ची को ही मतदान जागरूकता का माध्यम बना दिया गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ लोकतांत्रिक संदेश को जोड़ा जा रहा है।

स्थानीय निकाय चुनाव–2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन और चुनाव शाखा ने ग्रामीण मतदाताओं तक सीधे पहुंचने के लिए यह अभिनव तरीका अपनाया है। दरअसल, गांवों में बड़ी संख्या में लोग दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं और रोजाना दूध जमा कराने के दौरान उन्हें जो पर्ची (रसीद) दी जाती है, वही अब जागरूकता का सशक्त साधन बन गई है। इन पर्चियों पर 'मेरा वोट, मेरा अधिकार' जैसे संदेश प्रमुखता से छापे जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति को उसके मतदान के अधिकार और जिम्मेदारी का अहसास कराया जा सके। इस पहल की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय स्तर की सहकारी संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। Gopal Dairy के रजिस्ट्रार निखिल चावड़ा के अनुसार, प्रतिदिन करीब 20 हजार दुग्ध उत्पादकों को ऐसी पर्चियां दी जा रही हैं। पिछले पांच दिनों में ही 80 हजार से ज्यादा पर्चियां वितरित की जा चुकी हैं, जिनके जरिए मतदान का संदेश गांव-गांव तक पहुंच रहा है। यह संख्या अपने आप में इस अभियान की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाती है। प्रशासन ने इस संदेश को और प्रभावी बनाने के लिए एक रोचक तुलना भी पेश की है। जैसे दूध में 'फैट' का मूल्य तय करता है कि उसकी कीमत क्या होगी, उसी तरह एक वोट का मूल्य भी लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस सरल और सहज उदाहरण के जरिए ग्रामीणों को मतदान के महत्व को समझाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वे इसे केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में भी देखें।

डिजिटल माध्यमों का भी इस अभियान में भरपूर उपयोग किया जा रहा है। Amul Farmer App के जरिए रोजाना हजारों दुग्ध उत्पादकों को बल्क मैसेज भेजे जा रहे हैं। हर दिन करीब 4700 मोबाइल उपयोगकर्ताओं तक यह संदेश पहुंच रहा है, जबकि 16 अप्रैल से अब तक 15 हजार से अधिक जागरूकता संदेश प्रसारित किए जा चुके हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग सीधे पर्चियों तक नहीं पहुंच पाते, वे भी डिजिटल माध्यम से इस अभियान से जुड़ सकें। इस पूरे अभियान की अगुवाई जिला कलेक्टर और चुनाव अधिकारी डॉ. ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में की जा रही है, जो SVEEP (स्वीप) कार्यक्रम के तहत संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना और मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। 26 अप्रैल को होने वाले तालुका पंचायत, नगर पालिका और जिला पंचायत चुनावों का ग्रामीण क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में प्रशासन का यह प्रयास न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि यदि सोच नई हो, तो जागरूकता के साधन भी रोजमर्रा की जिंदगी से ही निकाले जा सकते हैं।

राजस्थान का "सार्थक नाम अभियान": स्कूलों में अपमानजनक नाम बदलने की पहल

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के उन नामों को सुधारने का प्रयास कर रही है जिनका अर्थ "छोटा", "काला", "शेर" और ऐसे ही अन्य नाम हैं। अब राजस्थान के स्कूलों में ऐसे नामों की अनुमति नहीं होगी। जी हां, भारत में छोटे बच्चों को दिए जाने वाले आम "प्यार के नाम" राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने "सार्थक नाम अभियान" शुरू किया है। विभाग का अनुमान है कि सरकारी और निजी स्कूलों में ऐसे 2000 से 3000 मामले हैं।

सरकार का दावा है कि यह पहल अनुचित, अस्पष्ट या नकारात्मक अर्थ वाले नामों को हटाने और उनके स्थान पर अधिक सार्थक और सम्मानजनक नामों को अपनाने के लिए शुरू की गई है। सरकार के अनुसार, काजोदामल, शेरू, कालू, टिंकू जैसे पारंपरिक नामों को कृष्ण, अथर्व, आरव और अखंड जैसे सम्मानजनक नामों से बदला जाना चाहिए। स्थानीय पहल समुदायों में सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं? मध्य प्रदेश के गांवों में स्थानीय पहल सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। अपशब्दों के विरुद्ध नियम लागू करके और राष्ट्रगान जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मान को बढ़ावा देकर, ये पहल अधिक सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण सामुदायिक वातावरण को बढ़ावा देती हैं। ऐसे बदलाव न केवल सार्वजनिक व्यवहार में सुधार लाते हैं, बल्कि हाशिए पर पड़े समूहों को भी सशक्त बनाते हैं। इससे समुदाय का समग्र कल्याण होता है। मंत्री ने कहा कि सरकारी अभिलेखों से जाति आधारित या अपमानजनक शब्दों को हटाना अत्यंत आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की : मंदिरों में भेदभाव का हिंदू धर्म और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले सप्ताह टिप्पणी की कि यदि मंदिर और मठ संप्रदाय के आधार पर प्रवेश प्रतिबंधित करते हैं और एक ही धर्म में संप्रदायों को अलग करते हैं, तो इसका हिंदू धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और समाज में विभाजन पैदा होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एम. वैदनाथन की इस दलील पर मौखिक टिप्पणी की कि संविधान का अनुच्छेद 26(ख) किसी धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है और यह अनुच्छेद 25(2)(ख) पर प्राथमिकता रखता है, जो राज्य को सभी सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने का अधिकार देता है।

केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में भगवान अय्यप्पा के भक्तों की ओर से वैद्यनाथन अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ने, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन और जॉयमाल्य बागची की पीठ सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति नागरत्ने ने कहा कि राज्य अनुच्छेद 25(2)(ख) के तहत हस्तक्षेप कर सकता है ताकि समाज के सभी वर्गों को मंदिरों में प्रवेश मिल सके। न्यायमूर्ति कुमार ने वैदनाथन से यह भी कहा कि इसीलिए हमने कहा था कि इस तर्क को बहुत ऊँचा न उठाएँ। उन्होंने वैदनाथन के इस तर्क का जिक्र किया कि अनुच्छेद 26(ख) अनुच्छेद 25(2)(ख) को निरस्त करता है। यदि इस तरह अन्य लोगों को बाहर रखा जाता है, तो यह हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। इसका धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह संप्रदाय के लिए प्रतिकूल होगा। यह धर्म के लिए अनुकूल होना चाहिए।

पश्चिम रेलवे दादर एवं हजरत निजामुद्दीन,के बीच चलाएगी एसी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उनकी बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए दादर एवं हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष किराये पर एसी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 04001/04002 दादर–हजरत निजामुद्दीन एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [26 फेरे]:

ट्रेन संख्या 04001 दादर – हजरत निजामुद्दीन स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को दादर से 00:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 21:35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। यह ट्रेन 23 अप्रैल से 16 जुलाई, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04002 हजरत निजामुद्दीन – दादर स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से 23:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 22:40 बजे दादर पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अप्रैल से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, मथुरा एवं कोसी कलां स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर श्रेणी के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04001 की बुकिंग 22.04.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे भूमि से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई एवं चोरी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई

(जीएनएस)। रेल सुरक्षा बल की अंकलेश्वर टीम द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए रेलवे भूमि पर लगे पेड़ों की अवैध कटाई एवं चोरी में संलिप्त 09 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 18.04.2026 को वडोदरा मंडल के कोसाड और गोठनगाँव रेलवे स्टेशनों के मध्य रेलवे भूमि से पेड़ों को काटकर चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात रेल सुरक्षा बल,अंकलेश्वर की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की गई, जिसमें 09 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से रेलवे के बबूल के पेड़ों की

लकड़ी बरामद की गई, जिसका कुल वजन 21,985 किलोग्राम तथा अनुमानित मूल्य 1,31,910/- है। इसके अतिरिक्त चोरी में प्रयुक्त 02 ट्रक, एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन तथा 02 कुल्हाड़ियाँ भी जब्त की गईं। इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3 रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 19.04.2026 को मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच रेल सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार 09 आरोपियों में से 02 को वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है, जबकि शेष 07 आरोपियों को माननीय रेलवे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है।

वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा हेतु इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सोना वायदा में 243 रुपये, चांदी वायदा में 1576 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 5 रुपये की नरमी

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 337413.93 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 18599.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 318813.5 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 37119 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2446.6 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 12155.60 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 153800 रुपये के भाव पर खूलकर, 153992 रुपये के दिन के उच्च और 153360 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153943 रुपये के पिछले बंद के सामने 243 रुपये या 0.16 फीसदी लुढ़ककर 153700 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 88 रुपये या 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 122744 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 11 रुपये या 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 15383 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 152064 रुपये के भाव पर खूलकर, 152600 रुपये के दिन के उच्च और 151920 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 33 रुपये या 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 152373 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 152505 रुपये के भाव पर खूलकर, 152847 रुपये के दिन के उच्च और 152110 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 152571 रुपये के पिछले बंद के सामने 72 रुपये या 0.05 फीसदी की बढ़त के साथ 152643 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 250428 रुपये के भाव पर खूलकर, 251969 रुपये के दिन के उच्च और 250210 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 252545 रुपये के पिछले बंद के सामने 1576 रुपये या 0.62 फीसदी की गिरावट के साथ 250969 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 721 रुपये या 0.28 फीसदी गिरकर 253202 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि

कमोडिटी वायदाओं में 18599.32 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 318813.5 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 12155.60 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37119 पॉइंट के स्तर पर

चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 745 रुपये या 0.29 फीसदी की गिरावट के साथ 253231 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। मेटल वर्ग में 2298.59 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 2.65 रुपये या 0.21 फीसदी की तेजी के संग 1272.05 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 3.45 रुपये या 1.01 फीसदी की मजबूती के साथ 343.9 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 1.5 रुपये या 0.41 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 366.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

जबकि सीसा अप्रैल वायदा 2.5 रुपये या 1.28 फीसदी की बढ़त के साथ 197.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4028.81 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 8104 रुपये के भाव पर खूलकर, 8212 रुपये के दिन के उच्च और 8022 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 5 रुपये या 0.06 फीसदी की गिरावट के साथ 8179 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 6 रुपये या 0.07 फीसदी औंधकर 8176 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 248.9 रुपये के भाव पर खूलकर, 251.7 रुपये के दिन के उच्च और 247.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 251.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 30 पैसे या 0.12 फीसदी की नरमी के साथ 251.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 30 पैसे या 0.12 फीसदी घटकर 251.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 993.9 रुपये के भाव पर खूलकर, 4.8 रुपये या 0.48 फीसदी की मजबूती के साथ 1008.5 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6436.41 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5719.19 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1528.95 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 355.89 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 64.60 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 342.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 2699.61 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1319.61 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.48 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9992 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61177 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27435 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 377316 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63001 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7991 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 26371 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 91763 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14075 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 39361 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 37104 पॉइंट पर खूलकर, 37141 के उच्च और 37104 के नीचले स्तर को छूकर, 72 पॉइंट घटकर 37119 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 24.5 रुपये की बढ़त के साथ 258.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 95 पैसे की नरमी के साथ 4.7 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 81 रुपये की गिरावट के साथ 569 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 869 रुपये की गिरावट के साथ 1580 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.05 रुपये की गिरावट के साथ 2.77 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.28 रुपये की गिरावट के साथ 1.04 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 18.5 रुपये की बढ़त के साथ 185.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 45 पैसे की नरमी के साथ 3.55 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 17.5 रुपये की गिरावट के साथ 351.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1 रुपये की बढ़त के साथ 384.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1050 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 10 पैसे की नरमी के साथ 0.27 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1 पैसे के सुधार के साथ 0.02 रुपये हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से अहमदाबाद में फिक्की के 100 वर्ष के उत्सव का शुभारंभ

▸▸ मुख्यमंत्री का फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रेरक संबोधन

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहलों से भारत आत्मनिर्भरता से विकास की राह पर दौड़ने लगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ विकसित भारत-2047 में विकसित गुजरात-2047 से गुजरात अग्रसर रहेगा

▸▸ सेमीकंडक्टर, ग्रीन ग्रोथ सहित इमर्जिंग सेक्टर्स में गुजरात को हब बनाने की मंशा है

▸▸ विकसित गुजरात-2047 रोडमैप से 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी तक ले जाने का लक्ष्य रखा है

▸▸ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वुमन-लेड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को साकार करने हेतु राज्य में महिला स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अहमदाबाद में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) की स्थापना के 100 वर्ष के उत्सव का शुभारंभ कराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में फिक्की के 100 वर्ष का उत्सव तथा देश का अमृतकाल फिक्की के लिए डबल बोनांजा है।

श्री पटेल ने फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रेरक संबोधन देते हुए देश के सबसे पुराने, प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली उद्योग मंच के रूप में फिक्की की 100 वर्ष की सफल यात्रा को मील का पत्थर बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहलों से भारत आत्मनिर्भरता से विकास की राह पर दौड़ने लगा है। इसमें भी फिक्की का उल्लेखनीय सहयोग मिला है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में गुजरात की विकास यात्रा की प्रभावी प्रस्तुति देते हुए कहा कि गुजरात ने देश और दुनिया को बताया है कि दृष्टिवान नेतृत्व तथा डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट से कितनी स्पीड और कितने स्केल के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात देश की जीडीपी में 8.3 प्रतिशत, नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 18 प्रतिशत और देश के कुल निर्यात में 27 प्रतिशत योगदान के साथ अग्रसर है।

उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए विकसित गुजरात-2047 का रोडमैप तैयार करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। इस रोडमैप अंतर्गत 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर, एआई तथा ग्रीन ग्रोथ जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स पर फोकस किया है। हाल ही में साणंद में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कराए गए दो सेमीकंडक्टर प्लांट्स द्वारा गुजरात अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। इतना ही नहीं; गिफ्ट सिटी में कार्यरत एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा सेंटर तथा फिनटेक राज्य को विभिन्न इमर्जिंग सेक्टर्स में अधिक मजबूत बनाएंगे। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आईटी तथा आईटीईएस पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी जैसी प्रोत्साहक नीतियों से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट तथा विश्व के उद्योगों के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बना है। आज विश्व की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 100 गुजरात में कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वुमन डेवलपमेंट नहीं, बल्कि वुमन-लेड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके अनुरूप गुजरात में महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में 'हर स्टार्टअप' प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है।

उन्होंने गुजरात को व्यापार-उद्योग के वर्ल्ड मैप पर प्रतिष्ठा दिलाने वाली वाइब्रेंट गुजरात समिट की सफलता में प्रारंभ से ही फिक्की के नेशनल पार्टनर के रूप में सहयोगी रहने की भी सराहना की।

उन्होंने प्रधानमंत्री के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को साकार करके विकसित भारत-2047 के निर्माण के लिए फिक्की के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

फिक्की के अध्यक्ष श्री अनंत गोयनका ने शताब्दी के लॉन्चपैड के रूप में अहमदाबाद के रणनीतिक चयन का उल्लेख करते हुए राज्य की उद्योगोन्मुखी नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रो-एक्टिव पॉलिसीज तथा निजी उपक्रमों के बीच समन्वय देश के अन्य राज्यों के लिए भी ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है।

उन्होंने कहा कि गुजरात ने सिद्ध किया है कि किस प्रकार राज्य सरकार की नीतियाँ आर्थिक लैंडस्केप को बदल सकती हैं। जिस प्रकार समग्र देश विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार फिक्की भी गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं तथा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है।

इस अवसर पर फिक्की की गुजरात राज्य परिषद् के अध्यक्ष श्री गोकुल जयकृष्णन ने स्टार्टअप्स तथा ग्रीन एनर्जी के लिए हब के रूप में राज्य की भूमिका पर बल दिया।

समारोह में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विजय शंकर, उपाध्यक्ष श्री पुनीत दालमिया, महासचिव श्री अनंत स्वरूप, महानिदेशक श्री ज्योति विज सहित फिक्की के पदाधिकारी, अग्रणी और उद्यमी उपस्थित रहे।

गर्मी में शीतलता, सौंदर्य और सेहत का खजाना: गोंद कतीरा का कमाल -शहनाज़ हुसैन

(जीएनएस)। गोंद कतीरा एक प्राकृतिक गोंद है जिसे गर्मियों के स्वास्थ्य बर्धक पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है । यह एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जो एस्ट्रैगलस पौधे की प्रजाति के रस को सुखाकर बनाया जाता है।। यह गम ड्रैगन या ट्रैगाकैंथ गोंद भी कहलाता है। सूखने पर यह छोटे, हल्के और थोड़े सख्त टुकड़ों के रूप में दिखाई देता है। इसका रंग आमतौर पर सफेद से हल्के भूरे रंग का होता है। यह बाहर से कठोर और सूखा दिखता है, लेकिन पानी में डालने से यह मुलायम, हल्के और पारदर्शी जेल की तरह फूलने लगता है। इसका हाइड्रेटिंग जेल रूप नमी बनाए रखने और त्वचा की लोच को अंदर से बाहर तक बढ़ाने में मदद करता है।

यह हलकी गंध और स्वाद का होता है । नियमित रूप में पेय के रूप में इसका सेवन करने से यह शरीर को ठंडक देता है, और पाचन शक्ति और एनर्जी भी बढ़ाता है. यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम से भरपूर होता है। इसमें अल्कलॉइड और लगभग 3% प्रोटीन होते हैं।

त्वचा और बालों के लिए उपयोगीः गोंद कतीरा शरीर में नमी बढ़ाता है, । फोड़े-फुंसियां होने के पीछे सबसे बड़ा कारण शरीर की गर्मी होती है । इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है और यह शरीर की गर्मी को कम करता है जिससे जिससे गर्मी के कारण होने वाले मुंहासे, फुंसियां और

ब्रेकआउट्स कम होते हैं। । इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की जलन को भी शांत करते हैं और कील मुहांसों को दूर करने में बहुत प्रभावी होते हैं । यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर पेट को ठंडा रखता है।कील मुहांसो से लड़ने के लिए गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स ड्रिंक काफी फायदेमंद माना जाता है ।इसके लिए 1 चम्मच गोंद कतीरा को रात भर थोड़े पानी में भिगो दें ताकि यह फूल जाए। 1 चम्मच सब्जा के बीज आधा घण्टा के लिए थोड़े पानी में भिगो दें।

1 गिलास नारियल पानी और थोड़ा सा नींबू का रस या शहद ले लें । एक कांच के कटोरे में गोंद कतीरा के जैल में भीगे हुए सब्जा के बीज डाल दीजिये । अब इसमें नारियल पानी मिलाएं और अंत में नींबू का रस या शहद मिला दें। इस ड्रिंक को आप सुबह दिन के किसी भी समय ले सकते हैं लेकिन खाली पेट लेने से अच्छे परिणाम मिलेंगे । नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपको कुछ ही हफ्तों में अपनी स्किन में फर्क महसूस होने लगेगा।

गोंद कतीरा को रातभर भिगो लें ।सुबह इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालें और इसके बाद आधा नींबू का रस मिला लें। इसे आप पी लें।इसके लगातार सेवन से कुछ ही दिनों में असर दिखना शुरू हो जायेगा । ये शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करके मुहांसे, झुर्रियों और सनबर्न जैसी समस्याओं को कम करता है जिससे त्वचा कोमल और आकर्षक दिखती है । भीगे हुए गोंद कतीरा के जेल को फेस पैक की तरह सीधे चेहरे लगा लें और आधा घण्टा बाद साफ़ पानी से धो डालें । मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा की जलन में आराम मिलता है।

गोंद कतीरा में एंटी-एजिंग गुण होते हैं। यह घाव भरने और दाग-धब्बों को कम करने के साथ-साथ पिम्पल्स को भी दूर करता है। इसके अलावा, इसके पोषक तत्व बालों को जड़ों से मज़बूत बना सकते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रेटिंग गुण स्कैल्प को ठंडक पहुंचाते हैं, बालों का टूटना कम करते हैं और रूखेपन से राहत दिलाते हैं। गोंद कतीरा में मौजूद पोषक तत्व बालों को जड़ों से मजबूत, घना और चमकदार बना सकते हैं। रात भर भीगे गोंद कतीरे को सुबह शर्बत या दूध के साथ लेने से भी बालों को अंदरूनी पोषण मिलता है।

'ऑपरेशन देव' सफल: चार राज्यों में फैले बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मासूमों की खरीद-फरोख्त का काला खेल उजागर

(जीएनएस)। अहमदाबाद/नई दिल्ली। देश को झकझोर देने वाले एक संगठित बाल तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गुजरात पुलिस ने 'ऑपरेशन देव' के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। यह ऑपरेशन केवल एक अपहरण मामले की जांच से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे परतें खुलती गईं, एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ, जो नवजात और नाबालिग बच्चों की खरीद-फरोख्त को अपना कारोबार बना चुका था। चार राज्यों में फैले इस नेटवर्क ने समाज के सामने एक गंभीर और भयावह सच्चाई रख दी है।इस पूरे मामले की शुरुआत चार वर्षीय बच्चे 'देव' के अपहरण से हुई थी। शुरुआत में यह एक सामान्य किडनैपिंग केस लग रहा था, लेकिन जांच के दौरान एक जुवेनाइल से मिली अहम जानकारी ने पुलिस को ऐसे सुराग दिए, जिन्होंने इस केस को राष्ट्रीय स्तर के बाल तस्करी नेटवर्क तक पहुंचा दिया। इसी के बाद इस मिशन को 'ऑपरेशन देव' नाम दिया गया और जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया गया।

तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल ट्रैकिंग और आधुनिक एआई टूल्स की मदद से पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना मुरुगन तक पहुंच बनाई, जिसे कागजनगर से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही करीमनगर क्षेत्र से तिरुपति, मल्लैया और गंगाधर नामक आरोपियों को भी

हिरासत में लिया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ ही यह साफ हो गया कि यह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध अपराध नेटवर्क है।

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह नवजात बच्चों को जन्म के महज 24 से 48 घंटे के भीतर ही बेच देता था। इस अमानवीय धंधे में अस्पतालों, दलालों और परिवहन के माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाता था, ताकि किसी को शक न हो। अब तक कम से कम आठ बच्चों की बिक्री की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि पुलिस को आशंका है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

इस नेटवर्क की जड़ें केवल एक राज्य तक सीमित नहीं थीं। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इन समन्वित कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था और राज्यों के बीच तालमेल बनाकर अपने नेटवर्क को मजबूत कर चुका था।

पुलिस के अनुसार, मुरुगन पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस बार की जांच में उसकी पत्नी कृष्णावेणी की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसे भी आरोपी बनाया गया है। यह तथ्य इस गिरोह की पारिवारिक और संगठित संरचना को दर्शाता है, जहां अपराध केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क के रूप में संचालित हो रहा था।

इस ऑपरेशन का एक अहम मोड़ तब आया जब पुलिस ने एक आरोपी को बस में एक बच्चे के साथ पकड़ा। यही गिरफ्तारी इस पूरे रैकेट की कड़ियों को जोड़ने में निर्णायक साबित हुई। इसके बाद एक-एक कर कई सुराग सामने आते गए और अंततः पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि बाल तस्करी जैसे अपराध केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह समाज के नैतिक ताने-बाने पर भी गहरा आघात हैं। ऐसे मामलों में अक्सर गरीब परिवारों की मजबूरी, जागरूकता की कमी और अपराधियों की चालाकी का फायदा उठाया जाता है।

फिलहाल, पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 'ऑपरेशन देव' ने न केवल एक बड़े अपराध का पर्दाफाश किया है, बल्कि यह भी उम्मीद जगाई है कि समय रहते कई मासूम बच्चों को इस भयावह जाल से बचाया जा सकेगा।

इस कार्रवाई ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के लंबे हाथ अब ऐसे संगठित अपराधों तक पहुंच रहे हैं, और बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

जनता की शिकायतों और समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का 'स्वागत' कार्यक्रम आगामी गुरुवार, 23 अप्रैल को आयोजित नहीं होगा

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2026 का राज्य और जिला स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम गुरुवार, 30 अप्रैल, 2026 को आयोजित होगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम आगामी गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को आयोजित नहीं होगा। राज्य में स्थानीय निकाय के चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को आयोजित होने वाला राज्य और जिला स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होने वाले इस 'स्वागत' कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल 2026 का राज्य और जिला स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम पांचवें गुरुवार यानी 30 अप्रैल,

2026 को आयोजित होगा।

इतना ही नहीं, उस दिन सुबह 8 से 11 बजे तक लोगों के अभ्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई के विशेष कार्य अधिकारी ने सभी संबंधित लोगों से 'स्वागत' कार्यक्रम के आयोजन में हुए इस बदलाव को ध्यान में लेने का अनुरोध किया है।

पश्चिम रेलवे द्वारा पालनपुर–अहमदाबाद खंड पर गति क्षमता बढ़ाने हेतु कार्य प्रगति पर

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा पालनपुर–अहमदाबाद रेलखंड पर ट्रेनों की गति क्षमता को 130 किमी/घंटा तक बढ़ाने के उद्देश्य से अवसंरचना सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में करजोड़ा–पालनपुर स्टेशनों के मध्य स्थित प्रमुख पुल संख्या 867 के अप्रोच पर जियो सेल एवं ब्लैंकेटिंग सामग्री डाली जा रही है। इस कार्य के पूर्ण होने पर इस खंड पर ट्रेनों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों का यात्रा समय कम होगा और वे अपने गंतव्य तक अधिक शीघ्रता से पहुँच सकेंगे। साथ ही, मालगाड़ियों की तेज एवं सुचारु आवाजाही से माल परिवहन प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी, जिससे समग्र रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। उक्त कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए दिनांक 21 अप्रैल 2026 (मंगलवार) को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 14822 (साबरमती–जोधपुर) दिनांक 22 अप्रैल 2026 को साबरमती–आबूरोड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा 24 अप्रैल को साबरमती–दुर्गापुर समर स्पेशल ट्रेन का संचालन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती–दुर्गापुर–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09413/09414 साबरमती–दुर्गापुर–साबरमती स्पेशल (विशेष किराया पर)

ट्रेन संख्या 09413 (साबरमती–दुर्गापुर स्पेशल) दिनांक 24 अप्रैल, 2026 को साबरमती से 18:25 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 09:15 बजे दुर्गापुर पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09414 (दुर्गापुर–साबरमती स्पेशल) दिनांक 26 अप्रैल, 2026 को 12:15 बजे दुर्गापुर से प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 03:00 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल एवं अण्डाल स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन सं. 09413 (साबरमती–दुर्गापुर स्पेशल) के लिए आरक्षण की बुकिंग 22 अप्रैल, 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

इस ट्रेन में 3-टियर एसी एवं स्लिपर श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक वर्ष की सजा और 1,47,006 का मुआवजा देने का आदेश

(जीएनएस)। अहमदाबाद, 22 अप्रैल, प्रतिनिधि द्वारा, चेक बाउंस से संबंधित कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच वित्तीय लेन-देन में विश्वास बनाए रखना है। इसलिए ऐसे मामलों में आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाकर हल्की सजा देना न केवल चेक आधारित लेन-देन में विश्वास को कमजोर करेगा, बल्कि कानून के मूल उद्देश्य को भी विफल कर देगा। ऐसे मामलों में अत्यधिक सहानुभूति दिखाना समाज में ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करने के समान माना जाएगा।

इसी प्रकार के एक चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में न्यायाधीश श्री एन. ए. कुलकर्णी ने यह गंभीर टिप्पणियाँ कीं और आरोपी अंजलि कैलाश गिधवाणी को एक वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को शिकायतकर्ता को 1,33,642 के चेक के

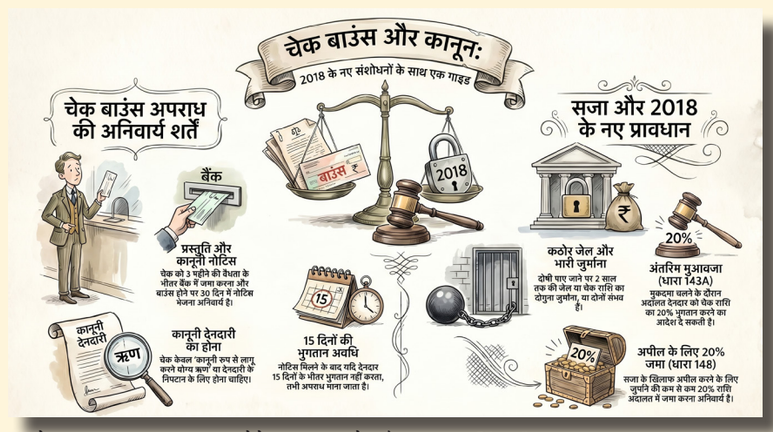

बदले 1,47,006 का मुआवजा देने का भी महत्वपूर्ण आदेश दिया।

शिकायतकर्ता SARVP फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. की ओर से अधिकृत अधिकारी मानस राम त्रिपाठी ने वकीलों ए. जे. सैयद, अजयसिंह बी. खारवड़, वाई. जे. त्रिवेदी, पी. एन. प्रजापति, के. एस. उटेकर, आर. जी. बंटुया और प्रियंका राठौड़ के माध्यम से मामले के तथ्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच हुए समझौते के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और वित्तीय जांच पूरी करने के बाद 2,00,000 से अधिक का ऋण दिया था।

लेकिन आरोपी ने निर्धारित समय के भीतर ऋण वापस नहीं किया। इसके अलावा, आरोपी ने एक्सिस बैंक, राजेंद्रनगर, बिलासपुर शाखा का 1,33,642 का चेक दिया था, जो बैंक में जमा करने पर अपर्याप्त शेष राशि के कारण बाउंस हो गया।

हिमाचल में निकाय चुनाव की दस्तक: 17 मई को मतदान, 51 शहरी निकायों में सियासी मुकाबला

शिमला। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश के 51 शहरी निकायों में 17 मई को मतदान कराया जाएगा। यह चुनाव न केवल स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के लिए एक बड़े शक्ति परीक्षण के रूप में भी देखे जा रहे हैं।

राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित समय में संपन्न कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी जिलों में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस चुनाव में कुल 51 शहरी निकाय शामिल हैं, जिनमें 4 नगर निगम—मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला—प्रमुख हैं। इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में भी मतदान कराया जाएगा। इन सभी निकायों में चुनावी सरगर्मियां अब तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राज्यस्तरीय राजनीति भी इसमें पूरी तरह से शामिल हो चुकी है।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार करीब 3.59 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें लगभग 1.80 लाख पुरुष और 1.79 लाख महिला मतदाता शामिल हैं, जो प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मतदान के लिए पूरे राज्य में 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां सुरक्षा और पारदर्शिता के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर परिषद और नगर पंचायतों के परिणाम मतदान के दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी। इस व्यवस्था के पीछे उद्देश्य यह है कि बड़े शहरी निकायों के परिणामों की गणना अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से की जा सके। राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। खासकर नगर निगम चुनाव, जो पार्टी चिन्ह पर लड़े जाएंगे, उनमें दोनों दल अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे, लेकिन इन पर भी राजनीतिक दलों का अप्रत्यक्ष प्रभाव साफ तौर पर देखा जाएगा। प्रदेश के चारों नगर निगमों का कार्यकाल 12 अप्रैल को समाप्त हो चुका था, जिसके बाद नए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए यह कार्यक्रम घोषित किया गया है। ऐसे में यह चुनाव प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए भी जरूरी हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन से लेकर मतदान तक की पूरी समय-सारिणी भी जारी कर दी है। इसके तहत उम्मीदवार 29, 30 अप्रैल और 2 मई को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को की जाएगी, जबकि 6 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 17 मई को मतदान होगा, जो पूरे चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। इस चुनाव के साथ ही पंचायत चुनावों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त ने संकेत दिया है कि पंचायत चुनावों की घोषणा फिलहाल लंबित है, लेकिन एक सप्ताह के भीतर इसकी रूपरेखा भी सामने आ सकती है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और भी अधिक सक्रिय होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के इन निकाय चुनावों को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मतदाताओं का रुझान यह संकेत देगा कि जनता मौजूदा सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है और विपक्ष को कितना समर्थन मिल रहा है।